

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 3क
PART II — SECTION 3A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7 -No. 7 नई दिल्ली, सोमवार, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935 (शक) NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2013/SHRAVANA 21, 1935 (SAKA) खण्ड XLIV Vol. XLIV

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खंड

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2013 / 21 श्रावण, 1935 (शक)

दादरा एंड नागर हवेली (सिविल कोर्ट्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स) अमेंडमेंट रेग्युलेशन, 2010 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपित के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT) OFFICIAL LANGUAGES WING

New Delhi, August 12, 2013/Shravana 21, 1935 (Saka)

The translation in Hindi of the Dadra and Nagar Haveli (Civil Courts and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulation, 2010 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विनियम, 2010

(2010 का विनियम संख्यांक 34)

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित।

दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए विनियम

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 240 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके द्वारा बनाए गए निम्निलिखित विनियम को प्रख्यापित करते हैं :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विनियम, 2010 है।
 - (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- 2. धारा 2 का संशोधन—दादरा और नागर हवेली (सिविल न्यायालय और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1963 (1963 का विनियम सं० 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
 - (i) उपधारा (1) में,—
 - (अ) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
 - (आ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड् रखे जाएंगे, अर्थात् :—
 - "(ख) सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) का न्यायालय ; और
 - (ग) सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय;";
 - (ii) उपधारा (2) में,—
 - (क) "सिविल न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर, "सिविल न्यायाधीशों" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे।
 - 3. धारा 5 का संशोधन-मूल विनियम की धारा 5 में, -
 - (i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
 - "(2) (क) जिला न्यायाधीश के न्यायालय और सिविल

न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) के न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार सिविल प्रकृति के सभी मूल वादों और कार्यवाहियों पर होगा:

- (ख) सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ प्रभाग) के न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार सिविल प्रकृति के ऐसे सभी मूल वादों और कार्यवाहियों पर होगा, जिनमें विषय-वस्तु एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की नहीं है।;"
- (ii) उपधारा (3) में, दोनों स्थानों पर आने वाले, "सिविल न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर "सिविल न्यायाधीशों" शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
 - "(4) सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद को ग्रहण या रजिस्टर नहीं करेगा, जिसमें केंद्रीय सरकार या दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या सरकार का कोई अधिकारी अपनी पदीय हैसियत में एक पक्षकार है:

परंतु दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस उपधारा के उपबंध उस आदेश में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी वाद या वाद के वर्ग या प्रवर्ग को लागू नहीं होंगे।

- (5) उपधारा (4) की कोई बात, सरकारी रेल के प्रशासन के विरुद्ध किसी वाद को लागू नहीं होगी।"।
- 4. धारा 6 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

- 5. धारा 7 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
 - "7. सिविल न्यायाधीश के न्यायालय की लघुवाद अधिकारिता—(1) उच्च न्यायालय, सिविल न्यायाधीश के किसी न्यायालय को, सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) के न्यायालय की दशा में, तीन हजार रुपए और सिविल न्यायाधीश (किनिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय की दशा में एक हजार पांच सौ रुपए से अनिधक ऐसे मूल्य तक के, जो वह उचित समझे, लघुवाद मामलों के विचारण के लिए प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) के अधीन लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता विनिहित कर सकेगा।
 - (2) उच्च न्यायालय, जब भी वह ठीक समझे, सिविल न्यायाधीश के किसी न्यायालय से इस प्रकार विनिहित ऐसी अधिकारिता वापस ले सकेगा।"।

- 6. धारा 8 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 8 में, "सिविल न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते है, "सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- 7. धारा 9 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 9 में, "सिविल न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर, "सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) या उसकी अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (किनष्ठ प्रभाग)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- 8. धारा 10 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 10 में, "सिविल न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर, "सिविल न्यायाधीशों" शब्द रखे जाएंगे।
- 9. धारा 11 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 11 में, "सिविल न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर, "सिविल न्यायाधीशों" शब्द रखे जाएंगे।

रामावतार यादव, उप विधायी परामर्शी, भारत सरकार।